

पीएम केयर्स के तहत वदेशी सहयोग को स्वीकृति

प्रिलमिंस के लिये:

पीएम केयर्स (PM-CARES)

मेन्स के लिये

आपदा प्रबंधन, COVID-19 से नपिटने हेतु भारत सरकार के प्रयास

चर्चा में क्यों?

हाल ही में [COVID-19](#) की चुनौती से नपिटने के लिये भारत सरकार ने 'प्रधानमंत्री नागरिक सहायता एवं आपातकालीन स्थिति राहत कोष (Prime Minister's Citizen Assistance and Relief in Emergency Situations or PM-CARES)' के तहत वदेशी सहयोग को स्वीकार करने का नरिणय लया है।

मुख्य बडि:

- सरकार के इस नरिणय के बाद अन्य देशों के नागरिक, संस्थाएँ और सरकार भी इस राहत कोष में अपना सहयोग कर सकेंगे।
- ध्यातव्य है कि भारत सरकार ने पछिले 16 वर्षों से आपदा प्रबंधन के लिये 'प्रधानमंत्री राष्ठीय आपदा कोष' (Prime Minister's National Relief Fund- PMNRF) के तहत कसिी भी प्रकार की वदेशी सहायता को स्वीकार नहीं कया था।
- हालाँक वर्तमान में केवल पीएम केयर्स (PM-CARES) के तहत ही वदेशी सहयोग/अनुदान की अनुमति दी गई है अन्य कसिी भी प्रकार के फंड या राहत कोष जैसे- PMNRF में वदेशी सहयोग पर अभी भी पाबंदी बनी रहेगी।

पीएम केयर्स (PM-CARES) फंड:

- पीएम केयर्स फंड की स्थापना 27 मार्च, 2020 एक सार्वजनिक धरुमार्थ ट्रस्ट (Public Charitable Trust) के रूप में की गई थी।
- देश का प्रधानमंत्री इस फंड का अध्यक्ष होगा तथा केंद्रीय गृह मंत्री, केंद्रीय रक्षा मंत्री और केंद्रीय वलित मंत्री भी इस फंड के सदस्य होंगे।
- इस फंड के तीन अन्य ट्रस्टियों को प्रधानमंत्री द्वारा नामति कया जाएगा, जो अनुसंधान, स्वास्थ्य, वज्जिान, सामाजिक कार्य, कानून, लोक प्रशासन और परोपकार (Philanthropy) के क्षेत्र में प्रतषिति व्यकृता होंगे।
- इस फंड के उद्देश्यों में सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल या कोई अन्य आपात स्थिति, आपदा या संकट, चाहे वह मानव नरिमति या प्राकृतिक, में कसिी भी प्रकार की राहत या सहायता पहुँचाना।
- इसमें स्वास्थ्य सेवा या दवा सुवधियों का नरिमाण या उन्नयन, अन्य आवश्यक बुनयादी ढाँचे, प्रासंगिक अनुसंधान या कसिी अन्य उद्देश्य के लिये आर्थिक सहायता उपलब्ध करना आदि शामिल है।

PMNRF के तहत वदेशी सहयोग स्वीकार का करने के कारण:

- वर्ष 2004 में हदि महासागर में आयी सुनामी के समय भारत सरकार ने प्रधानमंत्री राष्ठीय आपदा कोष के तहत कसिी भी प्रकार की वदेशी सहायता को लेने से इनकार कर दया था। हालाँक इस दौरान सहायता के इच्छुक राष्टर, वदेशी नागरिक आदि स्वयंसेवी संस्थाओं जैसे अन्य माध्यमों से सहायता भेज सकते थे।
- वर्ष 2004 में भारत सरकार की नीति में हुए इस बडे बदलाव के बाद अब तक इसका अनुसरण कया जाता रहा है।
- पछिले कुछ वर्षों में भारत ने अन्य क्षेत्रों में प्रगतिके साथ ही आपदा प्रबंधन और पुनरवास में अपनी क्षमता में महत्त्वपूर्ण वकिस कया है।
- वशिशज्जों के अनुसार, आपदा में राहत के अतरिकित वदेशी सहायता देने वाले देशों की अन्य राजनीतिक/रणनीतिक अपेक्षाएँ होती हैं, ऐसे में अन्य देशों से सहायता न लेने का नरिणय भारतीय वदेशि नीतिको मजबूती प्रदान करता है।
- हालाँक इस दौरान भारत ने अन्य देशों में आपदा या कसिी अन्य संकट की स्थिति में आर्थिक तथा अन्य आवश्यक सहायता उपलब्ध करायी है। उदाहरण- वर्ष 2005 में चक्रवात कट्रीना (Hurricane Katrina) के बाद अमेरिका को 25 टन राहत सामग्री की सहायता, वर्ष 2005 में

पाकस्तान को भूकंप से उबरने के लिये अन्य सहयोगों के साथ 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर की आर्थिक मदद, वर्ष 2008 चीन में भूकंप के बाद राहत सामग्री भेजी गई थी।

पीएम केयर्स के तहत वदेशी सहायता की स्वीकृति के कारण:

- COVID-19 महामारी से उत्पन्न चुनौतियाँ पहले कभी नहीं देखी गईं, किसी प्रमाणिक उपचार के अभाव तथा इस बीमारी की अनिश्चितता को देखते हुए सरकार ने 'पीएम केयर्स' के तहत वदेशी सहायता स्वीकार करने का फैसला लिया है।
- इस फंड की स्थापना से पहले कई वदेशी संस्थाओं, नागरिकों आदिने COVID-19 की चुनौती से निपटने में सरकार के प्रयासों में सहायता देने की इच्छा व्यक्त की थी।

नबिर्कष:

पछिले कुछ वर्षों में भारत ने आपदा-प्रबंधन के लिये स्वास्थ्य, तकनीकी और अन्य क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण प्रगतिकी है, देश में किसी आपदा के लिये PMNRF में वदेशी सहायता को स्वीकार न करना भारत को बनिा किसी दबाव के वदेशि नीति स्पष्ट करने में सहायता प्रदान करता है। परंतु वर्तमान में COVID-19 के कारण उत्पन्न हुई अनिश्चितता की स्थिति में सभी प्रकार की सहायता के लिये मार्ग खोलना इस आपदा से निपटने के प्रयासों को मज़बूती प्रदान करेगा।

सत्रोत: द इंडियन एक्सप्रेस

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/govt-to-accept-foreign-contribution-to-pm-cares-fund>

